

अब चीड़ की पत्तियां करेंगी मालामाल

कोयला और पट्टियां बनाने में मिली सफलता, सरकार देगी प्लांट लगाने पर 25 लाख तक की सबसिडी

चीड़ की पत्तियों के पर्यावरण अनुकूल उपयोग पर आई.आई.टी. मंडी में हुई वर्कशॉप



मंडी : कार्यशाला के बाद आई.आई.टी. मंडी की टीम और वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग सामूहिक चित्र में । (व्यू)

मंडी, 26 अक्टूबर (ब्यूरो): जंगलों में बेकार पड़ी चीड़ की पत्तियां अब आसपास के गांवों के लोगों को मालामाल करेंगी।

इससे कोयला और पट्टियां बनाने में सफलता मिली है और अब प्रदेश सरकार प्लांट लगाने पर 25 लाख तक की सबसिडी इसके लिए देने जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के सेंटर फॉर इनोवेटिव

टेक्नोलॉजी फार द हिमालयन रीजन पर्यावरण अनुकूल उपयोग पर एक ने पाइन (चीड़ की पत्तियां) के कार्यशाला में मंथन किया, जिसका

चीड़ की पत्तियों से कोयला और पट्टियां बनाने में सफलता मिली

चीड़ की पत्तियां (पाइन नीडल) बायो डिग्रेडेबल नहीं हैं और अत्यधिक ज्वलनशील भी हैं। इसलिए यह पूरे हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण, वन्य जैव विविधता और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हैं। सेंटर फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर द हिमालयन रीजन पिछले 3 सालों से सूखी पाइन नीडल से जंगलों में आग लगने की दुर्घटनाएं रोकने के कार्य में लगा है। अब संगठन ने शुद्ध पाइन नीडल से ब्रिकेट (ईट वाला कोयला) और पैलेट (पट्टियां) बनाने में सफलता हासिल की है। पाइन नीडल को अन्य बायोमास में मिश्रित करने में भी सफल रहा है। ये ब्रिकेट कम लागत पर अधिक ताप प्रदान करते हैं और लकड़ी या कोयले की तुलना में पर्यावरण को कम हानि पहुंचाते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयले के स्थान पर इन ब्रिकेट का कई छोटे व बड़े उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है। इनका उपयोग खाना पकाने में भी किया जा सकता है। पाइन नीडल के अतिरिक्त, इस मशीन का उपयोग लकड़ी के बुरादे, गन्ने की छाल, चावल के पुआल और गेहूं के पुआल के ब्रिकेट बनाने के लिए किया जा सकता है। सूखे पत्तों के जैव ईंधन का उपयोग भी ब्रिकेट बनाने के लिए किया जा सकता है।

हिमाचली लोगों को लाभ मिलेगा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चीड़ की पत्तियों (ड्राई पाइन नीडल) के उपयोग के बारे में जागरूकता लाना है और पाइन नीडल आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देना है।

बता दें कि सेंटर फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फार द हिमालयन रीजन को भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वित्तीय सहायता देता है। कार्यशाला में वन मंडल अधिकारी मंडी एस.एस. कश्यप और वन विभाग के प्रतिनिधि, औद्योगिक साझेदार इन्फीनिटी एनर्जी प्राइवेट

लिमिटेड दिल्ली, ए.सी.सी. सीमैंट, स्थानीय एवं सामाजिक समूह एफ.एम.सी., महिला मंडल, युवक मंडल और कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। वन मंडल अधिकारी मंडी एस.एस. कश्यप ने चीड़ की पत्तियों की वजह से वन में आग लगने की समस्या को सामने रखा और इसके हल के लिए आई.आई.टी. मंडी के प्रयासों को सरहनीय बताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा और जल्द से जल्द मशीन लगानी होगी। यह मानवता के हित में हमारा योगदान और जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण को दिशा में

बड़ा प्रयास होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार की इस सुविधा का जन-जन को लाभ मिले। लोग यह मशीन समूह और व्यक्तिगत स्तर पर बिना किसी परेशानी के स्थापित कर सकते हैं।

वनो को बचाना और पर्यावरण का संरक्षण किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज, सरकार और प्रौद्योगिकी संस्थानों के एकजुट प्रयास से यह अभियान सफल होगा। हमने पाइन नीडल के पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लिए कम लागत की तकनीक विकसित की है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न केवल सबसिडी की घोषणा की है, बल्कि इनके संग्रह के काम में मदद देने को भी तैयार है। हमें विश्वास है कि हम सबका यह एकजुट प्रयास एक सफल उद्यम का रूप लेगा, जिसके साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा।

- डा. आरती कश्यप, प्रधान परियोजना परीक्षक सेंटर फॉर अपलिफ्टिंग हिमालयन लाइवलीहुड (यू.एच.एल.)

एक इकाई के लिए 50 प्रतिशत, 25 लाख तक की सबसिडी की घोषणा

आई.आई.टी. मंडी परिसर में केंद्र का अपना ब्रिकेट और पैलेट उत्पादन संयंत्र है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पाइन नीडल आधारित संयंत्रों के लिए पूंजीगत व्यय पर एक इकाई के लिए 50 प्रतिशत, 25 लाख तक की सबसिडी की घोषणा भी की है। क्षेत्रीय वन पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्र देकर यह सहायता प्राप्त की जा सकती है।

यू.एच.एल. कार्यशाला में उपस्थित सहभागियों को मशीन का कामकाज समझाने के लिए सत्र के अंत में संयंत्र के कार्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया।